(ख) क्या इस वर्गीकरण से पूर्व संबंधित राज्यों से परामर्श किया गया था और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश को "सी" श्रेणी में रखे जाने के कारण इस राज्य के किसानों से "बी" श्रेणी के अंतर्गत रखे गये राज्य की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक प्रभार लिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या ये आरोप न्यायोचित है; और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य को "बी" श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया है; यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्री खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां। ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राजसहायता वितरण के लिए राज्यों को तीन श्रेणियों, क, ख और ग में रखा गया है। राज्यों का वर्गीकरण किसानों में जागरूकता के स्तर, राज्यों की ड्रिप विनिर्माता कम्पनियों से निकटता और राज्यों में ड्रिप सिंचाई की सम्भावना के आधार पर किया जाता है।

(ख) वर्गीकरण एक समिति जिसमें राज्यों, ड्रिप विनिर्माता संघ और "कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग" संबंधी राष्ट्रीय समिति के प्रतिनिधि थे, की सिफारिशों के आधार पर किया गया।

(ग) जी, नहीं। मध्य प्रदेश "ग" श्रेणी में है और "ख" श्रेणी वाले राज्य की तुलना में यहां मूल्य का अन्तर 10 प्रतिशत तक है।

(घ) विभिन्न श्रेणी में राज्यों के वर्गीकरण से ड्रिप घटकों का अधिकतम मूल्य निर्धारित होता है जिससे ऊपर विनिर्माता अधिक मूल्य नहीं ले सकता है। यह विचार है कि बाजार में प्रतिस्पर्द्धा से कुछ समय के उपरान्त घटकों की कीमतें कम होंगी।

(ङ) जी, हां। राज्यों के विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनःवर्गीकरण का मामला एक समिति को भेजा गया है। इस समिति के सदस्य राज्यों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, "कृषि में प्लास्टिक के प्रयोग" की राष्ट्रीय समिति और भारत सरकार से लिए गए हैं।

Formulation of National Farm Policy

3659. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:
SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to bring out a National Farm Policy; and

(b) if so, the details thereof and by when it is likely to be placed on the Table of the House?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) A Draft Agriculture Policy Resolution prepared by the Government was discussed in a meeting of State Agriculture Ministers held at New Delhi on 19th Feb., 1997. The major thrust of the draft Resolution is on:—

(i) removal of regional and crop imbalances;

(ii) increase in investment in the agriculture sector;

(iii) grant of facilities to agriculture as are available for industry without the regulatory and tax collection mechanism of the industrial sector;

(iv) making available inputs at resonable rates to the farmers in the proximity of their fields;

(v) easy availability of credit at resonable rates of interest to the farmers;

(vi) human resource development;

(vii) focus on agricultural research; and

(viii) relaxation of controls in agriculture sector.

The draft Resolution is under finalisation keeping in view the suggestions made in the Conference.